राज्य मंत्रियों की भूमिका

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल राज्य मंत्री अब अधिक उत्तरदायित्व का वहन कर सकेंगे. इस श्रेणी में आनेवाले कनिष्ठ मंत्रियों का कार्य कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग करना होता है, लेकिन यह लगभग परिपाटी बन गयी है कि अक्सर उन्हें कम महत्व के विभागीय काम, जैसे- राजभाषा से जुड़े मामले, संसद के अतारांकित प्रश्नों के उत्तर तैयार करना आदि- मिलते हैं. ऐसे में वे निर्णय करने की प्रक्रिया में अधिक योगदान नहीं कर पाते हैं. कैबिनेट मंत्री द्वारा राज्य मंत्रियों की अनदेखी की शिकायतें पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में आती रही थीं, पर अब इस स्थिति में ठोस बदलाव की संभावना है. कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हर संचिका राज्य मंत्री से होकर ही कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचे. इस निर्देश में यह भी आगाह किया है कि अति आवश्यक होने का आधार बना कर संचिका को सीधे कैबिनेट मंत्री के पास भेजने की कोशिश न हो. रिपोर्टों के अनुसार, शपथ ग्रहण के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से अपने विभाग के राज्य मंत्रियों को अधिक जिम्मेदारी देने को कहा था, ताकि वे सरकार के कामकाज को सीख सकें और उनमें दरकिनार होने का भाव न पैदा हो. प्रधानमंत्री का वह आग्रह अब औपचारिक तौर पर कैबिनेट सचिवालय द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया है. प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान भी इस तरह के निर्देश जारी हुए थे, पर उनका असर नहीं पड़ा था. कनिष्ठ मंत्रियों का दायरा संसद में लिखित उत्तर देने तक सीमित था और बहुत कम अवसरों पर ही उन्हें बोल कर जवाब या स्पष्टीकरण देने का अवसर मिला था. अहम बैठकों और निर्णयों में भी उनकी भागीदारी न के बराबर रही थी. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जब स्वयं प्रधानमंत्री कैबिनेट के सहयोगियों से कनिष्ठों के साथ जिम्मेदारी बांटने का आग्रह कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव होगा. इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ताजा निर्देश में एक नया हिस्सा जोड़ कर साफ कहा गया है कि संसद के तारांकित प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों समेत सभी संचिकाएं राज्य मंत्रियों से होकर ही कैबिनेट मंत्री की मेज पर आयेंगी. वर्तमान मंत्रिपरिषद में 33 राज्य मंत्री हैं, जिनमें नौ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिला है, पर उनमें से कुछ विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में भी योगदान दे रहे हैं. दोनों श्रेणियों में 17 नये चेहरे हैं. उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद की औसत आयु 60 वर्ष से नीचे है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, इसमें युवा ऊर्जा और प्रशासनिक अनुभव का मेल है. ऐसे में अगर राज्य मंत्रियों को अधिक जिम्मेदारी दी जाती है, तो न सिर्फ इससे उनकी क्षमता के विकास में मदद मिलेगी, बल्कि सरकार का प्रदर्शन भी बेहतर होगा. आशा है कि सरकार में सामूहिकता और सहभागिता बढ़ाने में यह सराहनीय पहल बहुत कारगर साबित होगी.

अगर राज्य मंत्रियों को अधिक जिम्मेदारी दी जाती है, तो इससे न सिर्फ उनकी क्षमता के विकास में मदद मिलेगी, बल्कि सरकार का प्रदर्शन भी बेहतर होगा.

बोधि वृक्ष

हावी इच्छाएं

जब तक कुछ हासिल करने की इच्छा है, कुछ उपलब्धि, कुछ होने की इच्छा है, भले ही वह किसी भी स्तर पर हो. तब तक, जब तक वहां पर क्षोभ, गुस्सा, शोक, भय होगा. अमीर होने की आकांक्षा, ये और वो होने की महत्वाकांक्षा तभी गिर सकती है, जब हम इस शब्द में निहित सड़ांध या महत्वाकांक्षा की भ्रष्ट प्रकृति को समझ लें. उन क्षणों में जब कि हम देख समझ लेते हैं कि ताकत, सत्ता हासिल करने की इच्छा, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह प्रधानमंत्री बन जाने की हो या जज या कोई पुजारी या धर्मगुरु, हमारी किसी भी प्रकार की शक्ति अर्जित करने की इच्छा आधारभूत रूप से पैशाचकीय या पाप है, लेकिन हम नहीं देख पाते कि महत्वाकांक्षा हमें भ्रष्ट करती है और यह भी कि शक्ति की ताकत की आकांक्षा वीभत्स है. इसके विपरीत हम कहते हैं कि हम शक्ति और ताकत को भले काम में लगायेंगे, जो कि निहायत ही बेवकूफाना वक्तव्य है. किसी भी गलत चीज से अंत में कोई सही चीज हासिल नहीं की जा सकती. यदि माध्यम या साधन गलत हैं, तो उनका अंजाम या उसके परिणाम भी गलत ही होंगे. यदि हम सभी महत्वाकांक्षाओं के संपूर्ण आशय को, उनके परिणामों, उसके परिणामों के साथ ही मिलनेवाले ऐच्छिक-अनैच्छिक परिणामों सहित नहीं जानते-समझते हैं और अन्य इच्छाओं के केवल दमन का प्रयास करते हैं, तो इस बात का कुछ भी अर्थ नहीं है. हम अपनी इच्छाओं के लिए पागल हुए जाते हैं, हम अपने आपको इच्छा द्वारा तुष्ट करना चाहते हैं. लेकिन, हम यह नहीं देखते कि वैयक्तिक सुरक्षितता की इच्छा, व्यक्तिगत उपलब्धि, सफलता, शक्ति, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आदि इन इच्छाओं ने इस संसार में क्या कहर बरपाया हुआ है. हमें यह अहसास तक नहीं है कि हम ही उन सब के जिम्मेदार हैं, जो हम कर रहे हैं. अगर कोई इच्छा को, उसकी प्रकृति को समझ जाये, तो उस इच्छा का स्थान या मूल्य ही क्या है? क्या वहां इच्छा का कोई स्थान है जहां प्रेम है? या जहां इच्छा हो, क्या वहां प्रेम के लिए कोई जगह बचती है?

जे कृष्णमूर्ति

सामाजिक मूल्य और राष्ट्रवाद

मनींद्र नाथ ठाकुर
एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू
manindrat@gmail.com

पिछले कुछ वर्षों में भारत में राष्ट्रवाद पर बहुत बहस हुई है. यहां तक कि बिना ठोस आधार के भी हम किसी को राष्ट्र-विरोधी होने का तमगा देने लगे हैं. इस आम चुनाव में राष्ट्रवाद ही सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन इस राष्ट्रवाद के उत्थान के दौर में हमारे समाज में मूल्य और नैतिकता गौण हो गयी. स्वतंत्रता संग्राम ने जिन सामाजिक मूल्यों को राष्ट्रवाद का अनिवार्य हिस्सा बनाया था, वे कहीं विलीन होते जा रहे हैं. शिक्षण संस्थाओं से लेकर अस्पतालों और नौकरशाही तक, परिवार से लाकर सामाजिक संगठनों तक, सब जगह यदि पुराने समय से तुलना करें, तो आप इस निष्कर्ष से सहमत होंगे. आज जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं, पहले हम उससे बेचैन हो जाया करते थे, लेकिन अब सामान्य-सी बात लगने लगी है. पहले किसी बेईमान व्यक्ति को लोग हिकारत की नजर से देखते थे, पर अब हमारी दृष्टि बदल गयी है. नायक को लेकर भी समाज की अवधारणा बदली है. जाहिर है, ऐसे में राष्ट्रवाद को लेकर भी नये प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं, जिस पर बहस लाजिमी है.

हम अक्सर कहते हैं कि जापान के राष्ट्रवाद से हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें वहां की राष्ट्रवादी अवधारणा को भी समझना होगा. उनके सामाजिक मूल्यों को देखें, तो आप आश्चर्य चकित हो जायेंगे. भूकंप के बाद जब परमाणु संयंत्रों से विकिरण की आशंकाएं पैदा हो गयीं और उससे जलसंकट पैदा हो गया, तो जापानियों ने आपसी सहयोग की मिसाल पेश की. हमारे यहां यदि जलसंकट हो जाए, तो हिंसा हो जाती है. विश्व युद्ध के बाद की क्षति के बावजूद यदि जापान उठ कर खड़ा हो पाया, तो यह उन सामाजिक मूल्यों के कारण है, जिसे हमें सीखने की जरूरत है.

उन्मादी विचार हिंसक होते हैं, किसी न किसी दुश्मन की खोज करते हैं, ताकि अपने उन्माद को मूर्त रूप दे सकें. यह दुश्मन यदि बाहर नहीं मिलता है, तो हिंसा आंतरिक हो जाती है. हमारे समाज में व्याप्त हिंसा उसी उन्मादी मन की अभिव्यक्ति है. इस उन्माद की जड़ में नयी उपभोक्तावादी संस्कृति और उसमें अपनी जगह नहीं बना पाने की हमारी असफलता है. इस संस्कृति की खासियत है कि आप कभी संतुष्ट ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका नारा है 'दिल मांगे मोर'. हम चाहतों के अंतहीन सिलसिले में फंस जाते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होने से हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि अपनी अस्मिता को उपभोक्ता होने की क्षमता से जोड़ लेते हैं. उसमें अक्षम होने से नपुंसक होने का एहसास होता है, जिससे निकलने के लिए हिंसक हो जाते हैं.

यह सही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति में मूल्यों की बात बेमानी हो सकती है, लेकिन मूल्यहीन समाज मनुष्य के रहने के लायक ही नहीं हो सकता है. सवाल है कि इस उन्मादी मन से समाज को निजात कैसे मिले? हमारा राष्ट्रवाद मूल्यवान और रचनात्मक कैसे हो?

इसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि समाज मूल्यवान लोगों को अहमियत दे. अपने राजनेताओं को भी इस बात की याद दिलाए कि वे गांधी के परंपरा के वाहक हैं. यदि सार्वजनिक जीवन में आये हैं, तो उसकी मर्यादा को भी समझें. समय आ गया है कि हम अपनी नयी पीढ़ी को उसके बारे में बताएं. हमारी युवा पीढ़ी इस सौभाग्य से वंचित है कि उनकी मुलाकात ऐसे मूल्यवान लोगों से हो सके, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिले.

स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे लोग थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर महानायक न भी हों, पर स्थानीय स्तर पर अपने मूल्यों के कारण जाने जाते थे. हर गांव, हर शहर में ऐसे अनेक लोग थे, जिनके बलिदान की गाथा, स्थानीय स्तर पर ही सही, लोककथा बन गयी थी. उनकी कमजोरियां भी रही होंगी, लेकिन उनकी खासियतों से ही समाज के मूल्य बने थे, जिसे हमें सीखना होगा. रेणु के मैला आंचल का 'बावनदास', जो मूल्यों के प्रति इतना प्रतिबद्ध था कि इसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी. समाज इन 'बावनदासों' से भरा था. हमें उनके जीवन को आदर्श के रूप में अपने समाज को लौटाना पड़ेगा.

मुझे ऐसे कई लोगों से मिलने का मौका मिला था, जिनसे मूल्यवान राष्ट्रवाद की झलक मिलती थी. ऐसे एक व्यक्ति थे बिहार के मुंगेरीलाल बाबू, जिनके राजनीतिक मूल्यों की दुहाई आज भी लोग देते हैं. कई बार मंत्री रह चुके मुंगेरीलाल की सादगी से कोई भी बाल मन प्रभावित हो सकता था. उनकी दूरदर्शिता देखिए कि उस समय मुंगेरलाल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, उसकी गूंज आज भी सुनायी देती है. वह पहले व्यक्ति थे, जिसने महिला, महादलित, अति पिछड़ा और गरीब लोगों के लिए आरक्षण में जगह देने की बात की थी और इसलिए नहीं कि इससे उनकी राजनीति चमकती, बल्कि इसलिए कि सही मायने में उन्हें सामाजिक न्याय की चिंता थी. वह आठवीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गये थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत पुस्तकालय देखने लायक था.

ऐसे ही फारबीसगंज के नेता थे सरयू बाबू, जिनको हर जाति, हर धर्म के लोग वोट देते थे. उनका जनसंपर्क देखने लायक था. कांग्रेस के समाजवादी धड़े से आते थे. फणीश्वर नाथ रेणु के मित्र भी थे और विरोधी भी. उनका व्यक्तिगत जीवन स्वतंत्रता संग्राम के उन्हीं मूल्यों को समर्पित था, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर रहे थे. भोला पासवान शास्त्री, कमलदेव नारायण सिन्हा, मोईनुल हक और कई ऐसे लोग थे, जो इतिहास के पन्नों से धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं. समाज अपने नायकों को भूलने लगा है.

जरूरी नहीं है कि गांधी-नेहरू जैसे महनायकों से ही समाज के सभी तबकों के लोग प्रेरणा ले सकें. जो नायक उनके नजदीक थे, उनके अपने समाज के थे, भले ही महानायक न हों, उनके माध्यम से भी हम समाज से संवाद कर सकते हैं. और, यह संवाद ही उन्मादी मन की दवा है. जगह-जगह जनतांत्रिक विचार मंच बनाये जाने की जरूरत है, ताकि यह संवाद हो सके.

बिहार-झारखंड के नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों ने दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों के साथ मिल कर कविताओं की अंत्याक्षरी का कार्यक्रम शुरू किया है. साथ में तय हुआ है कि कवियों के नाम पर बच्चे पेड़ भी लगाएं. ऐसे कार्यक्रमों से ही हम रचनात्मक राष्ट्रवाद की बात सोच सकते हैं. यदि शहर-शहर और गांव-गांव में हमारे बच्चे समाज के मूल्यवान लोगों, लेखकों, कवियों, अच्छे शिक्षकों, अच्छे डॉक्टरों के लिए पेड़ लगाने लगें, तो उसकी छाया में हमारी पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को सीख कर उन्हें आगे बढ़ा लेंगी.

जरूरी नहीं है कि गांधी-नेहरू जैसे महनायकों से ही लोग प्रेरणा ले सकें. जो नायक उनके नजदीक थे, भले ही महानायक न हों, उनके माध्यम से भी हम समाज से संवाद कर सकते हैं. संवाद ही उन्मादी मन की दवा है.

सरकार की कोशिशों पर करें भरोसा

डॉ सय्यद मुबीन जेहरा
शिक्षाविद
drsyedmubinzehra@gmail.com

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने हाल ही में नयी सरकार के रूप में पुरानी ही मोदी सरकार को चुन लिया है. नयी सरकार से वही पुरानी उम्मीद है कि वह देश को विकास की मंजिलों की ओर लेकर जायेगी और सभी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी. एक ऐसी सरकार की तरह काम करेगी, जो समर्थकों तथा विरोधियों, दोनों को एक नजर से देखेगी और विकास में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगी. दुनिया के सियासी माहौल में भारत की एक विशेष भूमिका मानी जा रही है और दुनिया की बड़ी ताकतें भी मानती हैं कि आनेवाला वक्त भारत का है. वह तेजी से आगे बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है. अब भारत दुनिया में अपने हिसाब से विषय तय करने में कामयाब होने लगा है.

मोदी सरकार के दोबारा आने के बाद अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर सवाल उठाये जा रहे थे. कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने इस सिलसिले में सरकार के किसी कदम से पहले ही मुसलमानों के नाम खुले खत तक लिख कर उनसे कहना शुरू कर दिया कि वे खौफ न खाएं. इस पर समझदार लोगों ने कहा कि ये लोग खुद ही अपने कारनामों के अंजाम से डरे हुए हैं, जिसे पूरे देश के मुसलमानों से जोड़ कर दिखाने की कोशिश की जा रही है. कुछ समझदार मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संस्थाओं ने मोदी-2 का स्वागत करते हुए अपनी बात रखी है, ताकि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करते हुए सभी भारतीयों का ख्याल रखे.

मोदी-2 सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े एलान करके हवा में घोली जा रही फिक्र और तनाव को दूर करने की कोशिश कर दी. इनमें जो एलान और मुद्दे हमें सीधे तौर से छूते हैं, वे शिक्षा से जुड़े हैं. इन पर सरकार अगर दिल के साथ जुड़ कर तमाम शक को दूर करते हुए काम करे, तो इसके सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो जायेंगे.

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और रोजगार एक जरूरी मुद्दा है. मोदी सरकार ने पांच करोड़ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप का एलान किया है. इस एलान से उम्मीद और भरोसे के नये रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं. सरकार ने स्कॉलरशिप के साथ मदरसा शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात कही है. हालांकि, मदरसे को लेकर जब सरकारें कुछ बदलाव की कोशिश करती हैं, तो एक तरह की घबराहट-सी पैदा कर दी जाती है, जबकि बहुत से मदरसे खुद अपने तौर पर नये जमाने के हिसाब से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनमें भी कहीं न कहीं कसर रह ही जाती है. अगर एक-दूसरे का विश्वास बनाये रखते हुए कुछ ऐसे बदलाव किये जाएं, जो आगे चल कर मदरसों का न सिर्फ सम्मान बुलंद करें, बल्कि यहां से पढ़नेवालों को रोजगार भी मिल सके, तो यह एक अच्छा कदम हो सकता है. वैसे अल्पसंख्यकों को शिक्षा रोजगार से जोड़ने और स्वावलंबी बनाने का अगर कोई काम सरकार करना चाहती है, तो उस वक्त तक इस का स्वागत करना चाहिए, जब तक सरकार की कोशिशों में कोई कमी न दिखाई दे जाये. अभी तो सिर्फ एलान हुआ है और अगर हम शुरू में ही इसका विरोध शुरू कर देंगे, तो फिर अल्पसंख्यकों के लिए कोई आगे बढ़ कर कैसे काम करेगा? अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विकास की रोशनी को हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. यह क्या सिर्फ सरकार की कोशिशों से मुमकिन होगा या मुस्लिम समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी? इस मुहिम का स्वागत करते हुए हमें सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि पांच करोड़ स्कॉलरशिप पानेवाले अल्पसंख्यकों में दूसरे धर्मों के लोग भी हैं. कहीं ऐसा न हो कि हम तो शक करते रह जाएं और दूसरे लोग इसका लाभ उठा लें.

आज की सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा. किसी भी दूसरे मजहब या समाज की तरह मुसलमानों को भी शिक्षा, रोजगार और सेहतमंद जिंदगी चाहिए. मुसलमानों को जिन शैक्षिक तथा रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया है, अब उन्हें वह मिलना ही चाहिए. हमारे समाज को सरकार की सच्ची नीयत वाले कामों का स्वागत करना चाहिए. आज मुस्लिम समाज के अंदर खुद को आगे बढ़ाने को लेकर जागरूकता लानी होगी. इसके लिए मुस्लिम समाज के पढ़े-लिखे जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा. कई लोग अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं. उन्हें किसी सरकारी सहायता का इंतजार नहीं है. हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए.

मदरसों में पढ़नेवाले विद्यार्थी नेकियों और अच्छाइयों को आगे बढ़ाते नजर आते हैं. आज जरूरत है कि उनको जो शिक्षा दी जा रही है, उसे रोजगार से भी जोड़ा जाए. उन्हें सरकारी संस्थानों में नौकरी के लिए तैयार किया जाए. बहुत जरूरी है कि धार्मिक शिक्षा के साथ वे तकनीकी शिक्षा भी हासिल करें. वे अच्छाइयों और धार्मिक शिक्षा को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए उनको रोजगार और खुशहाल जिंदगी देने के मौके बढ़ाने होंगे.

प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं. यह होना चाहिए. मदरसों के विद्यार्थियों के हाथ में दीनी शिक्षा और कुरान है, लेकिन आज उनको जरूरत है रोजगार की और सरकार के भरोसे की. मदरसों के उस्तादों के लिए भी सरकार को सोचना होगा. सबसे अच्छी कोशिश होगी अगर सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए, जो सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने पर सख्ती से नजर रखे और समय-समय पर उनका जायजा भी ले.

मदरसों में पढ़नेवाले विद्यार्थी नेकियों और अच्छाइयों को आगे बढ़ाते नजर आते हैं. आज जरूरत है कि उनको जो शिक्षा दी जा रही है, उसे रोजगार से भी जोड़ा जाए. उन्हें सरकारी संस्थानों में नौकरी के लिए तैयार किया जाए.

आपके पत्र

मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गरीब बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है. दो हफ्ते में 103 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है. 151 बच्चे भर्ती हैं, लेकिन सबसे अजीब बात है कि डॉक्टरों को न बीमारी का पता है, न दवा ही मालूम है. बंगाल में एक डॉक्टर के साथ मारपीट होने पर देशभर के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी. अब जब बिहार में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है, तो क्या पूरे देश के डॉक्टर उनके इलाज के लिए संगठित होंगे? सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य प्रशासन की सुस्ती और नाकामी का पता इसी बात से चलता है कि जब बच्चों की मौत पर बैठक चल रही थी, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मैच का स्कोर पूछ रहे थे. मामला चूंकि गरीब के बच्चों का है, इसलिए इस पर कोई न कैंडल जलने वाला है, न हड़ताल होने वाला. 25 साल से बीमारी हो रही है, पर किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. सबसे दुखद है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है.

गुलाम गौस आसवी, मदनाडीह, धनबाद

विदाई के हकदार थे युवराज

भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे रहे युवराज सिंह ने विश्व क्रिकेट को अलविदा कह कर अपने फैंस को भावुक कर दिया. सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर जगह बस युवराज की चर्चा है. किसी की जुबान पर उनके छह छक्कों की कहानी है, तो कोई 2011 के विश्वकप में उनके शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहा है. युवराज विश्व क्रिकेट के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम टी-20 इंटरनेशनल में एक ओवर की छह गेंदों पर छह छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अलावा, महज 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. उनके इस योगदान व प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें एक बेहतर विदाई दी जानी थी. टीम इंडिया के उप-कप्तान रोहित शर्मा तक ने ट्वीट के माध्यम से इस बात को मुखर किया है. इस दिग्गज खिलाड़ी के भारतीय क्रिकेट में योगदान को भूलना नामुमकिन है.

अमन सिंह, बरेली

लोस की सार्थकता नंबर गेम से आगे

प्रचंड बहुमत से सत्ता में आयी भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब नियमानुसार लोकसभा में विपक्ष की भूमिका में कोई दल नहीं है, यानी विपक्षी नेता की अनुपस्थिति में अपने व्यवहार में निरंकुशता न आने दे. कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में बैठने की शर्त तीन सीट कम होने की वजह से चूक गयी है. इस परिस्थिति में सत्तारूढ़ दल का व्यवहार निरंकुश होने का खतरा हमेशा रहेगा. यह बहुत कुछ पीएम पर निर्भर करता है कि वह इस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाये रखें. विपक्ष की गरिमा को बचाते हुए उनकी न्यायोचित मांग को कुचलने और मानमर्दित करने का प्रयास न करें. सभी गरीब, किसान, सामान्य जन के हित में सोच कर नीतियां बनाएं, उनका ईमानदारी से क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें. यह भाजपा व एनडीए की सरकार की 'अग्निपरीक्षा' है.

निर्मल कुमार शर्मा ,गाजियाबाद

कुछ अलग

आवेला असाढ़ मास, लागेला अधिक आस...

चंदन तिवारी
लोकगायिका
chandan.tiwari59@gmail.com

आसाढ़ सामने है. किसानों के जीवन में उल्लास लानेवाला महीना, जिसका इंतजार वे बेसब्री से करते हैं. खेती की शुरुआत इस महीने में होती है. इसी महीने मॉनसून आता है, बरखा-बुनी लाता है. खेतों और प्रकृति को नया जीवन मिलता है. नदी-तालाब अपने रंग में लौटने लगते हैं. आसाढ़ पर सावन का मनभावन होना टिका होता है. ऐसी कई विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से लोक का यह प्यारा मौसम है. आसाढ़ के बाद सावन आयेगा, तो बात कजरी की होने लगेगी. कजरी को सावन से जोड़ दिया जाता है और फिर कजरी पर जितनी बात होती है, उतनी बात आसाढ़ के गीतों पर नहीं होती, जबकि लोकगीतों की दुनिया में आसाढ़ सिर्फ खास और लोकप्रिय नहीं, बल्कि यह पहले महीने की तरह भी माना जाता है. लोकगीतों की दुनिया में एक सदाबहार, लोकप्रिय विधा है बारहमासा की. हिंदी इलाकों में जाएं, तो हर लोकभाषा में बारहमासा गायन की परंपरा रही है. बारहमासा का नाम लेते ही अपने देश में सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी की चर्चा होती है, जिन्होंने कालजयी बारहमासा की रचना की.

जायसी का बारहमासा महाकाव्य 'पद्मावत' का एक अहम हिस्सा है. जायसी ने बारहमासा में रत्नसेन की पत्नी नागमती की विरह-वेदना को स्वर दिया है. रत्नसेन जब चित्तौड़ छोड़ जाते हैं और नहीं आते हैं, तो नागमती को लगता है कि रत्नसेन किसी और के प्रेमजाल में फंस गये. वह एक-एक महीना इंतजार में गुजारती है. आशंका और उम्मीदों के साथ और उसी हर महीने को अलग-अलग छंदों में बांधा है जायसी ने. खास बात यह है कि जब जायसी नागमती के विरह को स्वर देते हैं, तो अपने बारहमासा में आसाढ़ से ही शुरुआत करते हैं. पहली पंक्ति है- *चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा. साजा विरह दुंद दल बाजा...* उनसे इतर बारहमासा की दुनिया में सब आसाढ़ को ही विरह और उम्मीदों का पहला महीना मानते हैं.

भोजपुरी में के कालजयी नाटक 'बिदेसिया' में लोकनट सम्राट भिखारी ठाकुर ने एक बारहमासा रचा है. उसकी शुरुआत भी आसाढ़ से ही होती है- *आवेला असाढ़ मास, लागेला अधिक आस, बरखा में पिया घरे रहतन बटोहिया...* भिखारी ठाकुर के बाद पुरबिया उस्ताद और भोजपुरी लोकगीतों के राजकुमार महेंदर मिसिर ने भी शानदार बारहमासा रचा है. वे लिखते हैं- *गरजत आसाढ़ मास, पिया नहीं आयो पास...*

मैथिली में थोड़ी विविधता आती है, लेकिन आसाढ़ केंद्र में ही होता है. महाकवि विद्यापति ने भी खूब बारहमासा रचे. एक बारहमासा उनका बेहद लोकप्रिय है- *प्रीतम हमरो तेजने जाइ छी परदेशिया यौ, धरबै जोगनीक भेष... असाढ़ पुरि गेल बारह मास यौ, धरबै जोगनीक भेष...* विद्यापति आसाढ़ को आखिरी माह के रूप में लाते हैं. अधिकतर बार पहले महीने की तरह, तो कहीं-कहीं यह आखिरी माह के रूप में भी आता है, लेकिन आसाढ़ लोकभाषाओं की दुनिया में, विशेषकर बारहमासा में एक खास महीना बनकर उभरता है. इस आसाढ़ पर अगर लोकगीतों की दुनिया में और विचरें, तो एक से एक गीत मिलते हैं.

देश दुनिया से

अदालत में सुनवाई के दौरान मुर्सी का निधन

मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का अदालत में एक सुनवाई के दौरान निधन हो गया. वे 67 साल थे. मुर्सी लोकतांत्रिक रूप से चुने गये मिस्र के पहले राष्ट्रपति थे. हालांकि, एक साल बाद ही सेना ने उनका तख्तापलट कर दिया था. मिस्र के सरकारी टीवी ने कहा है कि सोमवार को अदालत की सुनवाई के दौरान पूर्व राष्ट्रपति अचानक गिर पड़े. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया. उनके वकील के मुताबिक, उन्हें काहिरा में दफनाया गया. बताया जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई. मुर्सी के खिलाफ जासूसी के एक मामले में मुकदमा चल रहा था. रिपोर्टों के मुताबिक सुनवाई के दौरान वह अपनी दलील देने के बाद ही गिर पड़े. मुर्सी मिस्र के सबसे ताकतवर इस्लामी कट्टरपंथी गुट मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य थे, जो अब प्रतिबंधित संगठन है. साल 2013 में वह लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होनेवाले देश के पहले राष्ट्रपति बने. लेकिन, अब्देल फतह अल सीसी के नेतृत्व में सेना ने उनका तख्तापलट कर दिया. पूर्व राष्ट्रपति कई बार अदालत का सामना कर चुके थे. उनके खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाने और ईरान के लिए जासूसी करने जैसे आरोपों में मुकदमे चलते रहे हैं.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है